- 20th Year
- Issue: 78
- 16.07.2026 (THURSDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा आज, तैयारी पूरी, जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने जारी किया अनुष्ठान कार्यक्रम

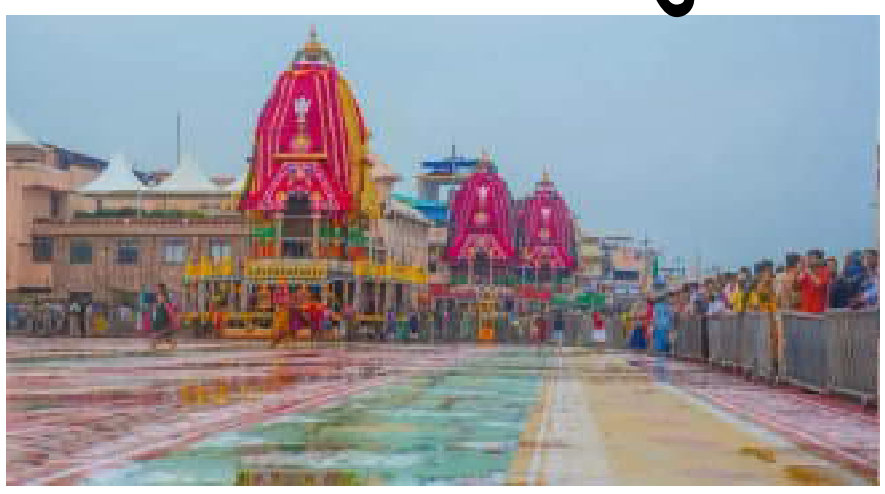

पुरी १५/०७ (संवाददाता): ओडिशा के पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा 2026 के लिए अनुष्ठान कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस वर्ष भव्य रथ यात्रा का आयोजन गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने यात्रा को सुचारु और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। समय और कैलेंडर मंदिर प्रशासन के अनुसार, रथ यात्रा के दिन धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत सुबह 6 बजे मंगल आरती के साथ होगी। इसके बाद मंदिर परिसर में परंपरा के अनुसार कई महत्वपूर्ण पूजा और अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। इन धार्मिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को विधिवत रूप से उनके-अपने रथों तक ले जाया जाएगा।

पुरी की रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचते हैं। इस आयोजन में भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सुबह से शुरू होंगे धार्मिक कार्यक्रम मंदिर प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, रथ यात्रा वाले दिन सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना शुरू हो जाएगी। मंगल आरती के बाद भगवान की दैनिक पूजा परंपराओं को पूरा किया जाएगा। इसके बाद देवताओं को रथों पर विराजमान करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

रथ यात्रा से पहले कई महत्वपूर्ण रस्में निभाई जाती हैं, जिनका धार्मिक महत्व काफी अधिक होता है। मंदिर के सेवक और पुजारी निर्धारित परंपराओं के अनुसार सभी अनुष्ठानों को पूरा करते हैं। तीनों रथों पर विराजेंगे भगवान रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ, भगवान बलभद्र तालध्वज रथ और देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ पर सवार होती हैं। इन रथों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है और हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचकर इन्हें आगे बढ़ाते हैं।

रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। इसे भगवान की मौसी के घर जाने की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद भगवान वापस मु य मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां रथ यात्रा में बड़ी सं या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारी कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष योजना बनाई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्थानों पर सहायता केंद्र और अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है। सदियों पुरानी इस परंपरा में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल होते हैं।भौगोलिक संदर्भ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का पर्व माना जाता है। इस दौरान जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह रथ यात्रा की तारीख घोषित होने के साथ ही श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया है। पुरी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। श्री जगन्नाथ मंदिर की यह वार्षिक रथ यात्रा एक बार फिर आस्था और परंपरा का भव्य प्रदर्शन करेगी। 16 जुलाई को होने वाले इस आयोजन के लिए पुरी पूरी तरह तैयार हो रहा है और देश-दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक धार्मिक उत्सव पर रहेंगी।

मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, किसानों और नौजवानों को दी बड़ी सौगात

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में देश की विनिर्माण क्षमता, बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन और समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हम आपको बता दें कि कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहने वाली इस योजना के तहत भारत में मोबाइल फोन निर्माण पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर प्रमुख कंपोनेंट्स की खरीद पर अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत और भारतीय ब्रांडों द्वारा डिजाइन एवं अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि योजना अवधि में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन होगा, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा करीब 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह योजना पीएलआई योजना के बाद भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी।

साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को और गति देने के लिए सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को भी 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी। यह कार्यक्रम चिप डिजाइन, मशीनों एवं कच्चे माल के निर्माण, नए फैब स्थापित करने, एटीएमपी/ओसैट इकाइयों के विस्तार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास जैसे छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा।

सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाना है। अब तक सेमिकॉन 1.0 के तहत 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 105 स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी कैबिनेट ने दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी। पहली परियोजना के तहत एनएच-19 से वाराणसी रिंग रोड तक गंगा तट के समानांतर 46.04 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण 14,447.64 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

भारत में चलेंगी फ्लाईंग बसें-नितिन गडकरी

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): एक तरफ जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के केंद्र में हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश की मोबिलिटी को बदलने के लिए अपने अगले बड़े आइडिया पर काम शुरू कर दिया है।

यह नया विचार है भारतीय शहरों के लिए उड़ने वाली बसें। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने देश के तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एक इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हिस्से के रूप में लाइंग बसें शुरू करने की योजना का एलान किया। समारोह में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि जल्द ही, मैं लाइंग बसें (उड़ने वाली बसें) शुरू करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही ऐसे सीप्लेन ला चुका हूँ जो पानी पर उतर सकते हैं। मैंने खुद भी एक सीप्लेन को समुद्र में लैंड कराया था। अब मेरे मंत्रालय के तहत, मैं बिजली से चलने वाला एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करूँगा।

ईसीआई ने दिल्ली, पंजाब समेत चार राज्यों में वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाई

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): चुनाव आयोग ने दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न के तहत गिनती की अवधि और अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली और कर्नाटक में, गिनती की अवधि 29 जुलाई से बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी गई है। वोटर लिस्ट का ड्रा ट अब 17 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि पहले इसकी समय-सीमा 5 अगस्त थी। दावे और आपत्तियां 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकेंगी और फ़ाइनल लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जो पहले तय तारीख 7 अक्टूबर से बारह दिन बाद है। पंजाब में, बूथ लेवल अधिकारियों (ञ्झह्य) द्वारा गिनती के लिए घर-घर जाकर जानकारी जुटाने की समय-सीमा 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और ड्रा ट वोटर लिस्ट 13 अगस्त को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 13 अगस्त से 12 सितंबर तक होगा और फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना में, घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम 3 अगस्त तक जारी रहेगा। ड्रा ट वोटर लिस्ट 10 अगस्त को जारी की जाएगी और 10 अगस्त से 9 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

प्रचारअभियान और चुनाव

इससे पहले, 14 जुलाई को हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए गिनती की अवधि 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। वोटर लिस्ट का ड्रा ट 31 जुलाई को जारी किया जाएगा और वोटर लिस्ट का फ़ाइनल प्रकाशन 3 अक्टूबर को तय किया गया है।

ममता का भाजपा पर प्रहार, आप चाहते हैं मुझे हार्टअटैक आए, पर मैं आपका अंत देखूंगी

कोलकाता १५/०७ (संवाददाता): तृणमूल कांग्रेस (ञ्झष्ट) की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (ञ्झछक्क) पर निशाना साधा। उन्हें एक और झटका तब लगा जब विधायक मदन मित्रा बागी खेमे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, जो जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं और साथ ही कहा कि उनके पास ञ्झछक्क के लिए एक संदेश है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी चाहती थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि मुझे हार्ट अटैक आए, लेकिन मैं तब तक ज़िंदा रहूँगी जब तक आपका अंत न देख लूँ। बुधवार को मित्रा ने ममता का खेमा छोड़कर रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ़ विधानसभा में अपना कमरा बदला है।

विविध समाचार

आम कार मालिक खुद नहीं नाप सकते माइलेज, केवल डीलर की मशीनें बताएंगी सच-गडकरी

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): देश में इथेनॉल-ज़्लेंडेड (श्व20) पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि कोई भी आम कार मालिक खुद अपनी गाड़ी की ज़्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) का सही अंदाजा नहीं लगा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाहन चालकों को इसके लिए अधिकृत डीलरों के टेस्टिंग उपकरणों (मशीनों) पर ही भरोसा करना चाहिए। सोमवार को,क्क्क न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में गडकरी एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। पत्रकार ने दावा किया था कि सरकार के अनिवार्य श्व20 पेट्रोल पर स्विच करने के बाद शहर में गाड़ी चलाने पर उनकी कार का माइलेज काफी कम हो गया है। जब पत्रकार ने बताया कि 2023 में खरीदी गई और संभवत: श्व20 के अनुकूल उनकी कार का माइलेज हाल ही में 11 किमी/लीटर से घटकर 7 किमी/लीटर हो गया है, तो गडकरी ने सवाल किया कि यह आंकड़ा कैसे निकाला गया। उन्होंने डैशबोर्ड पर दिखने वाले माइलेज डिस्प्ले का ज़िक्र करते हुए जवाब दिया, मैंने इसे अपनी कार में चेक किया, जैसे हर कोई करता है। इस पर गडकरी, जिन्होंने इथेनॉल-ज़्लेंडिंग प्रोग्राम का पुरज़ोर बचाव किया है, ने फिर कहा कि ज़्यूल एफिशिएंसी की सही रीडिंग केवल निर्माता-अधिकृत टेस्टिंग इक्विपमेंट (उपकरणों) से ही मिल सकती है।

उन्होंने कहा, आप और मैं माइलेज चेक नहीं कर सकते। कार का माइलेज केवल कंपनी-अधिकृत डीलर की मशीन का इस्तेमाल करके ही चेक किया जा सकता है।यह बातचीत केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है कि श्व20 पेट्रोल कुछ गाड़ियों में ज़्यूल इकॉनमी को 3-5त्न तक कम कर सकता है, हालांकि सरकार ने अपनी ज़्यूल पॉलिसी का बचाव भी किया।पिछले हफ़्ते, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल ज़्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए एक सवाल-जवाब वाला डॉज़्यूमेंट जारी किया। इसमें सरकार ने माना कि श्व20 पेट्रोल कुछ

गाड़ियों में ज़्यूल एफिशिएंसी कम कर सकता है, लेकिन तर्क दिया कि माइलेज ही एकमात्र पैमाना नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा, यह सच है कि कुछ गाड़ियों में ज़्यूल इकॉनमी में 3-5त्न की कमी आ सकती है। लेकिन माइलेज केवल एक पैमाना है। केंद्र ने इथेनॉल ज़्लेंडिंग बढ़ाने, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन में कटौती करने के अपने प्रयासों के तहत 1 अप्रैल से पूरे देश में श्व20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी थी।हालांकि, इसे वाहन मालिकों से विरोध का सामना करना पड़ा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कुछ वर्गों में चिंता भी पैदा हुई है। कार मालिकों का कहना है कि माइलेज कम हो रहा है, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने पुरानी गाड़ियों में ज़्लेंडेड ज़्यूल (मिश्रित ईंधन) के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए हैं।

पूरी तरह से नहीं। लेकिन उन्हें काफी हद तक सही अंदाज़ा मिल सकता है। मॉडर्न कारें ज़्यूल इकॉनमी का हिसाब इंजन में डाले गए ज़्यूल, तय की गई दूरी और इंजन कंट्रोल यूनिट (श्वष्ट) से मिलने वाले इनपुट जैसे डेटा का इस्तेमाल करके लगाती हैं। हालांकि डैशबोर्ड की रीडिंग सिर्फ़ एक अंदाज़ा होती है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से, फुल टैंक पर की गई मैन्युअल कैलकुलेशन के मुकाबले ये अज़्सर 2-5त्न के दायरे में ही होती हैं। ऑटोमोटिव एज़्सपर्ट्स आम तौर पर फुल-टैंक मेथड को असल दुनिया का सबसे सटीक टेस्ट मानते हैं। ड्राइवर टैंक भरते हैं, ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं, अगली बार टैंक भरवाने तक सामान्य रूप से गाड़ी चलाते हैं, और फिर तय की गई दूरी को भरे गए ज़्यूल की मात्रा (लीटर) से भाग देते हैं। मैन्युफैक्चरर का डायग्नोस्टिक टूल सिर्फ़ ज़्यूल इकॉनमी दिखाने से कहीं ज़्यादा काम करता है। यह श्वष्ट से डिटेल्ड डेटा पढ़ता है और चेक करता है कि ज़्यूल इंजेज़्टर, ऑज़्सीजन सेंसर और एयरज़्लो सेंसर जैसे पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यह इंजन की खराबी का पता भी लगा सकता है और श्वष्ट कैलिब्रेशन को वेरिफ़ाई कर सकता है, जिससे ज़्यूल की खपत पर असर पड़ सकता है।हालांकि, यह हर तरह की ड्राइविंग कंडीशन में असल दुनिया के माइलेज को सीधे तौर पर नहीं मापता है। ज़्यूल इकॉनमी पर ट्रैफ़िक, शहर बनाम हाईवे पर ड्राइविंग, एयर-कंडीशनिंग का इस्तेमाल, टायर प्रेशर, ड्राइविंग का तरीका और गाड़ी पर लोड जैसी चीज़ों का भी असर पड़ता है। असल में, गाड़ी का ऑनबोर्ड डिस्प्ले एक काम का अंदाज़ा देता है, जबकि फुल-टैंक मेथड असल दुनिया की ज़्यूल इकॉनमी का काफ़ी हद तक सही माप देता है। डीलर के डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल मुज़्य रूप से ज़्यूल एफिशिएंसी पर असर डालने वाली मैकेनिकल या इलेज़्ट्रॉनिक दिक्कतों का पता लगाने के लिए किया जाता है, न कि माइलेज का पता लगाने के एकमात्र सही तरीके के तौर पर।

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ई२० पेट्रोल की समीक्षा की मांग की

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुज़्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन गाड़ियों के लिए श्व20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, जो इथेनॉल-मिश्रित ईंधन पर चलने के लिए नहीं बनी हैं। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि पुरानी गाड़ियों में श्व20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज कम हुआ है, इंजन जल्दी खराब हो रह

नेता ने पेट्रोल पंपों से कहा कि वे ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और श्व20-ज़्लेंडेड ज़्यूल में से चुनने का विकल्प दें। उन्होंने श्व20 पेट्रोल की कीमत कम करने की भी मांग की और तर्क दिया कि इस ज़्यूल की कैलोरीफ़िक वैल्यू कम होने के कारण माइलेज कम मिलता है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से श्व20 ज़्यूल की कीमत कम करने की अपील की है; ज़्योंकि श्व20 से माइलेज कम मिलता है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए... मैंने उनसे मिलने का समय भी मांगा है।

उन्होंने श्व20 पेट्रोल की वजह से परेशानी झेल रहे लोगों से कहा कि वे अपनी बात डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म पर रखें। उन्होंने ज़ोर दिया कि सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिए लोगों की आवाज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो इन समस्याओं से परेशान हैं कि वे वीडियो बनाएँ और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, ज़्योंकि यह सरकार हमारी बात इतनी आसानी से नहीं सुनेगी। राजनीतिइससे पहले शनिवार को, केजरीवाल ने दिल्ली में एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन का दौरा किया ताकि श्व20-ज़्लेंडेड पेट्रोल के असर के बारे में गाड़ी मालिकों से बात कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ईंधन के बारे में सरकार के दावे उपभोक्ताओं के अनुभव से मेल नहीं खाते हैं।

पाकिस्तान की टीमें भारत में ड्रग्स तस्करी करती थीं-पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि का बड़ा खुलासा

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीमें और प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे के दौरान नियमित रूप से ड्रग्स की तस्करी करते थे। मनी ने खास तौर पर शोएब अज़्तर और मोहज़्मद आसिफ का नाम लिया। ये दोनों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (क्क्ष्टक्क) ने 2006 में बैन लगाया था, ज़्योंकि वे प्रतिबंधित पदार्थ %नैंड्रोलोन% के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। क्क्ष्टक्क ट्रिज़्यूनल के नतीजों के बाद अज़्तर पर दो साल का बैन और आसिफ पर एक साल का सस्पेंशन लगाया गया था। उनके डोप टेस्ट सितंबर 2006

में पॉजिटिव आए थे, जिसके कारण 17 अज़्टूबर को जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच से पहले उन्हें पाकिस्तान की टीम से हटा दिया गया था।

2006 से 2010 तक गृह मंत्रालय में काम करने वाले मणि ने,द्बद्ध को बताया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अज़्तर और मोहज़्मद आसिफ़ के मामले की जानकारी दी है, जिन्हें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने तब वापस भेज दिया था जब उन्होंने खुद माना कि वे ड्रग्स साथ ले जा रहे थे। यही वह चाल है। तो यही पूरी पृष्ठभूमि है। जब भी पाकिस्तानी टीमें और प्रतिनिधिमंडल भारत आए, तो उन्होंने यहाँ ड्रग्स की तस्करी की।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में ड्रग्स भेजना पाकिस्तान की आधिकारिक नीति है। वे जाने-माने लोग हैं। वे हाई-प्रोफाइल लोग हैं। पाकिस्तान टीम के दूसरे लोग भी ऐसे ही थे, जिनके नाम शायद सामने नहीं आए, लेकिन पूरी टीम ऐसी ही थी और वे ऐसा करते थे। मणि ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच बॉब वूल्मर की संदिग्ध मौत को भी ड्रग तस्करी के खिलाफ उनके विरोध से जोड़ा। 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में आयरलैंड से पाकिस्तान की हार के कुछ समय बाद, 18 मार्च 2007 को जमैका के किंग्स्टन में वूल्मर की मौत हो गई थी। वे अपने होटल के कमरे में बेहोश पाए गए थे और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मणि ने कहा कि उनके इंग्लिश कोच बॉब वूल्मर, जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा की जा रही ड्रग तस्करी का विरोध किया था, की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर देखना होगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ड्रग्स साथ लाते थे। और उस समय ष्ठद्ब के अनुमान के मुताबिक, भारत में आतंकी हमलों के लिए 30त्न फंडिंग ड्रग्स से ही आती थी। उन्होंने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (ष्ठद्ब) के 2006 के एक अनुमान का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि भारत में आतंकी हमलों के लिए लगभग 30त्न फंडिंग ड्रग्स के कारोबार से आती थी।

पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए का एक्शन, हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

नयी दिल्ली १५/०७ (संवाददाता): 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक अहम घटनाक्रम के तहत, जज़्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 6 जुलाई को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है, जिसमें सईद को आरोपी बनाया गया है और आरोप लगाया गया है कि वह 22 अप्रैल, 2025 को हुए उस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। वारंट की मांग करते हुए आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने अदालत से कहा आरोपी जानबूझकर गिरज़्तारी से बच रहा है और एनआईए उससे इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू करने और किसी भी आगे की जांच में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनिश्चित तिथि का गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध करती है। अपने

आवेदन में एनआईए ने तर्क दिया कि सईद इस समय पाकिस्तान में है और भारतीय अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उसे पाकिस्तान से वापस लाने के सभी कानूनी रास्ते लगभग खत्म हो चुके हैं और इसलिए उसके शारीरिक रूप से मौजूद न होने पर भी न्यायिक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। एनआईए के मुताबिक, पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और सईद ने इस साजिश को अंजाम देने में मुज़्य भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने उसे भारत के खिलाफ हुए कई पुराने आतंकी हमलों से भी जोड़ा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (क्चहृस्स्) के तहत, यदि कोई आरोपी भारत से बाहर है, जानबूझकर अदालत में पेश होने से बचता है और गंभीर अपराधों के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, तो अदालतें उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चला सकती हैं। इस तरह का मुकदमा शुरू होने से पहले, अदालत को समन और वारंट जारी करना आवश्यक है। यदि आरोपी फिर भी पेश नहीं होता है, तो उसे घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रह सकती है।एनआईए की पहली चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों - सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी - के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैबा के ऑपरेटिव साजिद सैफुल्लाह जट्ट और पहलगाम निवासी बशीर है अहमद और परवेज अहमद को आरोपी बनाया गया था

बस्तर की धरती से उखड़ने वाली हैं नज़्सलियों की जड़ें! विदा होगा गन और ग्रेनेड का दौर, डिप्टी सीएम का बड़ा एलान

बस्तर १५/०७ (संवाददाता): छज़्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल से सशस्त्र नज़्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए एक निर्णायक समयसीमा (ष्ठद्गड्डस्रद्यद्बठ्ठद्ग) निर्धारित की है। मंगलवार को विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उपमुज़्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि राज्य से 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नज़्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके एक साल बाद, यानी 31 मार्च 2027 तक बस्तर में तैनात अधिकांश केंद्रीय बलों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

शर्मा ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जब 31 मार्च 2026 को सशस्त्र नज़्सलवाद के समापन की तिथि तय की गई, तब यह भी निर्णय लिया गया था कि 31 मार्च 2027 तक यहां तैनात केंद्रीय बलों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुछ बल उससे पहले भी वापस जा सकते हैं। बैठकों में इस बात पर सहमति बनी है कि 31 मार्च 2027 को हम एक निश्चित समय सीमा मानकर चलें, हालांकि इसमें थोड़ा आगे-पीछे

हो सकता है। उन्होंने बताया कि विज़ीय वर्ष 2026-27 के लिए पुलिस विभाग के मुज़्य बजट में कुल 7,721.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शर्मा ने बताया कि पुनर्वास करने वाले वामपंथी उग्रवादी नज़्सली कैडर के पुनर्वास के लिए केंद्र की पुनर्वास नीति के तहत सावधि जमा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नज़्सल प्रभावित जिलों में 15 नए थानों की स्थापना के लिए 975 नए पद सृजित किए जाएंगे।

उपमुज़्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही आठ पुलिस चौकियों को थानों में उन्नत करने के लिए 337 नए पद और कम बल स्वीकृत वाले 21 थानों में अतिरिक्त बल वृद्धि के लिए 870 नए पदों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की 16 जेलों में 'प्रिजन कॉलिंग सिस्टम' स्थापित करने के लिए 1.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से वॉयस या वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकेंगे। शर्मा ने कहा कि इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुज़्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हर कोई चाहता है कि नज़्सलवाद समाप्त हो और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक नज़्सलवाद समाप्त हो जाएगा।

बघेल ने कहा, 31 मार्च में अब केवल 21 दिन शेष हैं। हमें उज़्मीद है कि इसके बाद अर्धसैनिक बलों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।ञ्ज उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नज़्सलवाद के समाप्त होने के बाद 31 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसका जश्न मनाया जाना चाहिए और बस्तर के विकास का लाभ मुज़्य रूप से स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए।

बघेल ने चर्चा के बाद कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। कटौती प्रस्ताव बजट में पेश की गई अनुदान मांगों में से किसी विशेष मांग की राशि को कम करने के लिए लाया जाने वाला एक विधायी प्रक्रिया है। प्रस्ताव के विरोध में 37 और पक्ष में 24 मत पड़े, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसके बाद सदन ने शर्मा के विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

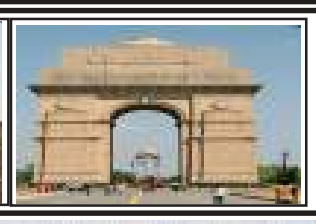

विविध समाचार

आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना पेश करती है टियांजिन बिनहाई लाइब्रेरी

चीन में एक ऐसी लाइब्रेरी है, जिसे देखने के बाद आपकी निगाहें उसी पर टिकी रहेंगी। आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना पेश करती इस लाइब्रेरी का नाम है 'टियांजिन बिनहाई लाइब्रेरी' जिसकी खूबसूरती देख आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, कि ये एक लाइब्रेरी है। यहां कुछ लोग तो सिर्फ फोटो के लिए ही इस लाइब्रेरी का रूख करते हैं। बता दें, इस लाइब्रेरी को चीन के 'नेशनल डे' को आम जनता के लिए खोला गया है। 37, 000 स्कायर फीट तक फैली टियांजिन बिनहाइ लाइब्रेरी में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस लाइब्रेरी की उंचाई करीब पांच मंजिल के बराबर बनी हुई है। यहां पर पढ़ने के लिए हर जॉनर करीब 12 लाख से भी ज्यादा किताबें मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी में लगभग हर जॉनर में 12 लाख किताबें हैं। इस लाइब्रेरी को बिनहाई कल्चरल सेंटर में खोला गया है, जिसे उच कंपनी एमवीआरडीवी ने डिजाइन किया है। इस खूबसूरत चीन की लाइब्रेरी में एक बेहद ही यूनिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी आख बनी हुई है, इस आंख के डिजाइन पर अंदर होने वाली चीजों और बाहर बने पार्क की परछाई पड़ती रहती है, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है।

- इस लाइब्रेरी में तकरीबन हर जॉनर की 12 लाख किताबें हैं.
- शहर के बिनहाइ कल्चरल सेंटर में खुले इस लाइब्रेरी को उच कपनी एमवीआरडीवी ने डिजाइन किया है.
- इस लाइब्रेरी में सर्विस स्पेस, बुक स्टोरेज, आर्काइव, कंप्यूटर रूम, ऑडियो रूम, ऑडिटोरियम, लाउंज, मीटिंग रूम, ऑफिस और रीडिंग स्पेस भी है.
- इन किताबों और लाइब्रेरी के बीच एक बहुत बड़ी आख भी बनी हुई है. – इस आंख पर अंदर होने वाली चीजों और बाहर बने पार्क की परछाई पड़ती रहती है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है.
- इसे चीन के नेशनल डे पर आम जनता के लिए खोल दिया गया.

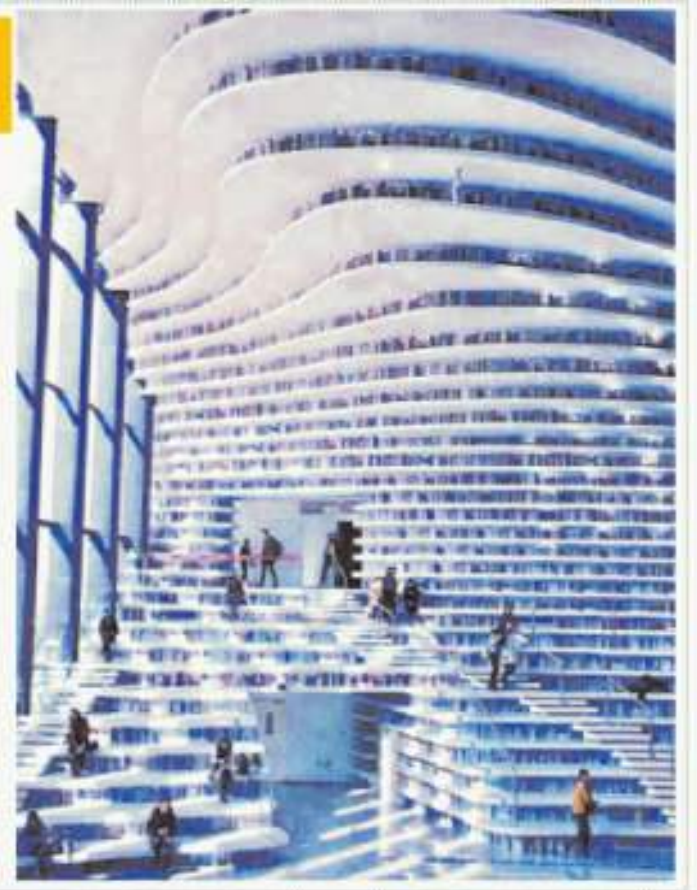

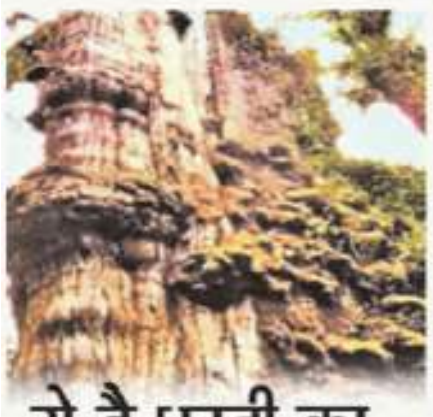

ये है धरती का सबसे पुराना पेड़

महाभारत से पहले का है इसका इतिहास

इस दुनिया में एक नही बल्कि कई सारी गजब की जगह और चीज मौजूद है जो लोगों को हैरान कर देती है। पेड़ हम इंसानों के लिए कितने जरूरी है यह बात तो सभी जानते हैं। अगर इस धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो इंसान का जीना संभव नही है। जब भी पुराने पेड़ों की बात निकलती है तो अक्सर लोगों को बरगद का पेड़ याद आता है। लोग यही कहते है की बरगद के पेड़ सालों साल जीते हैं और यह सबसे पुराने होते है। लेकिन आज हम आपको इस दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में बताते है जो हजारों साल पुराना है। दुनिया के इस सबसे पुराने पेड़ की बात करें तो यह चिली में पाया गया है, जो लगभग 5000 साल से ज्यादा पुराना है। साइप्रस ट्री के नाम से पहचाने जाने वाला यह पेड़ ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों ने इसलिए नाम इसलिए दिया है क्योंकि यह धरती पर मौजूद सबसे पुराना पेड़ है।

कितने साल का है पेड़

इस पेड़ की उम्र की बात करें तो यह 5484 साल का है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यह 6000 साल से ज्यादा पुराना है। यह 13 फिट चौड़ा और 26 मीटर लंबा है। इस पर लगातार शोध चल रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसने जलवायु परिवर्तन के साथ खुद को किस तरह से अनुकूल रखा।

हासिल किए ये खिताब

ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ चिली के एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में मौजूद है। जिस कैलिफोर्निया के पाइन पेड़ को हराकर सबसे पुराना पेड़ होने का खिताब अपने नाम किया है। धरती के इस सबसे पुराने पेड़ में लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। अक्सर लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं।

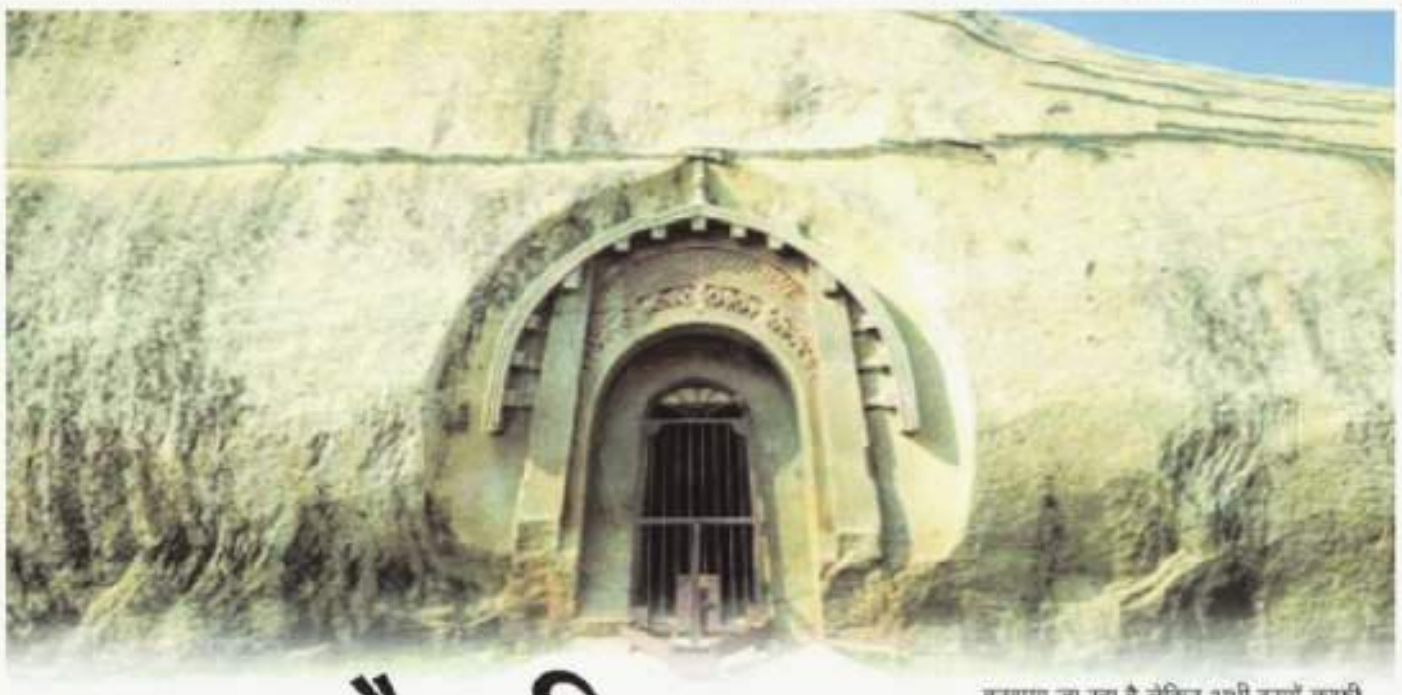

आस्था और इतिहास का खूबसूरत संगम है वाणावर की गुफाएं!

आप सभी जानते होंगे कि पहले आदिमानव के जमाने में गुफाएं उनके रहने का स्थान हुआ करती थी। वह समय ऐसा था जब गुफाएं उन लोगों के लिए एक सुरक्षित घर हुआ करती थी। इतना ही नहीं गुफाएं अलग-अलग मौसम से बचाने का काम करती थी। जंगली जानवर से लोगों की रक्षा किया करती थी। उन गुफाओं के बारे में जानना और वहां जाना अपने आप में बहुत खास है। आज हम एक ऐसी गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो आस्था और इतिहास का एक खूबसूरत संगम है। वह गुफा है वाणावर की गुफाएं।

वाणावर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। वाणावर की पहाड़ियों पर स्थित यह गुफाएं भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यह गुफाएं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी और अजीव संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल थी।

गुफाओं के पास है सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर

वाणावर की गुफाओं में एक शिव मंदिर भी स्थित है। जिसे सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सातवीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह बिहार के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यह वाणावर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सावन के महीने में इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वैसे तो प्रत्येक दिन लोग यहां जल चढ़ाने आते हैं। लेकिन सावन के महीने में यहां का वातावरण ही कुछ और होता है।

वाणावर गुफाओं की विशेषताएं

- वाणावर की गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है। इन गुफाओं में कुल सात गुफाएं हैं। इनमें से चार गुफाएं वाणावर पहाड़ियों पर और तीन गुफाएं नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित है।
- इन गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण शिल्प और मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ शिल्प और मूर्तियां इतनी सुंदर है कि वह आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है।
- इन गुफाओं में बुद्ध, बुद्धिसत्व और अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियां है इनके अलावा इन गुफाओं में कई अन्य शिल्प भी है जिनमें पशुओं, पक्षियों और फूलों की मूर्तियां आदि शामिल है।
- दिन पर दिन इन गुफाओं को और भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी स्तर पर काम चल रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है।
- यहां हर साल वाणावर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में लोग बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लेते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने में लोगों को आसानी हो इसके लिए सीढ़ियां भी बनवाया जा रहा है लेकिन अभी इसमें काफी समय लग रहा है।

वाणावर की गुफाओं का महत्व

वाणावर की पहाड़ियों पर कुल सात गुफाएं है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। यह गुफाएं प्राचीन इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। गुफाओं में मौजूद शिल्प और मूर्तियों से हमें बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान होती है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहां हर साल हजारों लोग इन गुफाओं को देखने और उनकी प्राचीन संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए दूर-दूर से आते हैं। इन गुफाओं को हजारों साल पहले पहाड़ों को सावधानी से काटकर बनाया गया था। इन गुफाओं की दीवारें बहुत चिकनी है। आपको बता दें, इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर ही सम्राट अशोक के अभिलेख है। यह लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए है, जिसे गाइड पढ़कर विस्तार से बताते और समझाते हैं।

सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई थीं गुफाएं

वाणावर की पहाड़ियों पर कुल सात गुफाएं है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। इनमें चार वाणावर पहाड़ियों पर और तीन पास में ही नागार्जुन की पहाड़ियों पर है। पहाड़ों को सावधानी से काट कर हजारों साल पहले इंसान इस बेहद सुंदर गुफाओं को बनाया। इनमें से कई गुफाओं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी चिकनाई आज के समय में लगाई जाने वाली टाइल्स से कम नहीं है। मौर्य काल की यह स्थापत्य कला पर्यटकों को आश्चर्य से भर देती है। इनका निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। इसमें कर्ण चौपर, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा अपनी स्थापत्य कला के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर ही सम्राट अशोक के अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि के जानकार इसे पढ़ और समझ पाते है। गाइड इसके बारे में विस्तार से बताते है।

इन गुफाओं में है मौर्यों का खजाना, आज भी दबे हैं यहां कई रहस्य

बिहार की धरती काफी ऐतिहासिक रही है। इस धरती पर जहां कई शूरवीरों ने जन्म लिया और एक नई इबारत लिखी, वहीं प्राचीनता की बात करें तो बिहार में कई ऐसी धरोहर हैं, जो दुनिया भर में लोकप्रिय रही हैं। इन्हीं में से एक धरोहर है बराबर की गुफाएं। ये गुफा भारत की ऐसी सबसे पुरानी गुफा है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यही नहीं, इनमें मौर्य काल की वास्तुकला और शिलालेख आज भी मौजूद हैं।

कहां है ये गुफाएं...

- ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- इन गुफाओं को 'सतघरवा' भी कहते हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल (322–185 ईसा पूर्व) से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है।
- ये गुफाएं बराबर (चार गुफाएं) और नागार्जुनी (तीन गुफाएं) की जुड़वां पहाड़ियों में स्थित हैं।
- अधिकतर गुफाएं दो कक्षों की बनी है जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है।

कौन-कौन सी हैं गुफाएं...

बराबर पहाड़ी में हैं ये चार गुफाएं...

- लोमस ऋषि गुफा
- सुदामा गुफा
- करण चौपर
- विश्व झोपरी

नागार्जुन गुफा

- गोपी गुफा
- भायक गुफा
- वैदतिका गुफा

अन्दर से कैसी हैं बराबर गुफाएं...

गुफाओं की एंट्रेस वॉल और दरवाजों पर कई शिलालेख हैं, जो बताते हैं कि यहां कभी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये गुफाएं मगरमच्छ के समान नजर आने वाली चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। गुफाओं में बने कमरे के इंटीरियर में पॉलिश है, जो आज भी सुरक्षित है।

चट्टानों को काटकर बनाए गए कमरे

चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कमरे अशोक (273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व) और उनके पुत्र दशरथ के मौर्य काल, तीसरी सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को पनपने का अवसर दिया।

इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के संन्यासियों द्वारा किया गया था जिनकी स्थापना मक्खाली गोसाला द्वारा की गयी थी, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे।

कलिंग समाचार

गुरूवार 16 जुलाई 2026

ट्रंप का असली चेहरा सामने आया

शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने की तमन्ना लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने %ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व% चलाकर वेनेजुएला पर शनिवार स्थानीय समय के अनुसार 02ः01 बजे हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया लोरेस समेत गिर तार कर लिया और उन्हें हवाई मार्ग से अमेरिका ले आया गया। अमेरिकी विमान से मादुरो को जब उतारा जा रहा था तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हथकड़ियां भी लगी थीं। यह दृश्य देखकर इतिहास खुद को दोहराता है, वाली मिसाल याद आ गई। लेकिन यह नहीं पता था कि इतिहास इतनी जल्दी दोहराया जाएगा। अभी 21वीं सदी शुरु ही हुई थी कि इराक पर अमेरिका ने विनाशकारी हथियारों की तलाश के नाम पर आक्रमण किया और तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन को गिर तार कर फांसी पर भी चढ़ा दिया। फिर पता चला कि ऐसे कोई हथियार इराक में थे ही नहीं। शायद अमेरिका को हथियारों की तलाश थी भी नहीं, उसे इराक के प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा चाहिए था, जो उसे मिल गया। यही खेल अब वेनेजुएला में खेला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर गलत तरीके से सत्ता हथियाने का आरोप लगाने के साथ ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उनका कहना है कि अब मादुरो को पत्नी समेत अमेरिका की कड़ी न्याय व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। मानो सारी दुनिया का ठेका अमेरिका को मिल चुका है कि उसका राष्ट्रपति जब चाहे किसी संप्रभु देश पर आक्रमण कर दे और वहां के नेता को अमेरिकी कटघरे में खड़ा कर दे। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों, स्त्री अधिकार को ठेंगा दिखाते हुए राष्ट्र प्रमुख के साथ उनकी पत्नी को भी गिर तार कर ले। चिंता की बात यह है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जिन उद्देश्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को बनाया गया था, वह पूरी तरह नख–दंत विहीन और लाचार बन चुकी है। घर के अशक्त बूढ़े बुर्जुग उपद्रवी बच्चों को मत लड़ो–मत लड़ो जैसी लाचारगी भरी नसीहत देते हैं, वैसा ही हाल संरा का हो चुका है। पूरी दुनिया में अमेरिका समर्थित हमले हो रहे हैं और संरा बयान जारी करने से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इससे बेहतर है कि संरा को मिटा कर नए सिरे से कोई ऐसी वैश्विक संस्था बनाई जाए, जो वाकई दुनिया में शांति स्थापना का काम कर सके। लेकिन इसकी पहल कौन करेगा ये भी विचारणीय है। जब भारत में प.जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया तो तीसरी दुनिया के देशों को अपने अस्तित्व और स मान को बचाए रखने के लिए नया मंच मिला। आज के भारत का हाल तो ऐसा है कि ट्रंप पचासों बार पाकिस्तान के समकक्ष हमें रखते हुए युद्धविराम के दावे कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी माई डियर फ्रेंड ट्रंप का नाम ही जपते रहे। अब भी वेनेजुएला के घटनाक्रम पर नरेन्द्र मोदी की कोई सीधी टिप्पणी देखने नहीं मिली है, बल्कि एस जयशंकर का बयान आया है कि हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के ज़रिए और शांतिपूर्ण तरीक़े से किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत को बताना चाहिए कि सभी संबंधित पक्षों से उसका तात्पर्य क्या है। क्यों मोदी पहले चीन का नाम लेने से कतरा रहे थे और अब अमेरिका को सीधे नहीं कह रहे कि उसका इस तरह आक्रमण करना गलत है। मान लें कि निकोलस मादुरो ने अपने देश में कुछ गलत किया है या वैश्विक स्तर पर किसी अपराध में संलग्न हैं, तो उन पर कार्रवाई के लिए उनके अपने देश की न्याय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय अदालत है। ट्रंप यहां किस हैसियत से घुसे हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने बिल्कु ल ठीक कहा है कि वेनेजुएला के नेता को हिंसक तरीक़े से पकड़ना पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक और बेहद ख़तरनाक मिसाल है। क्यूबा ने कहा कि वेनेजुएला पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग करता है। रूस ने भी इस हमले को गलत बताया है वहीं चीन ने कहा है कि एक संप्रभु देश के ख़िलाफ़ अमेरिका के खुलेआम बल प्रयोग और उसके राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ कार्रवाई से वह बहुत हैरान है और इसकी कड़ी निंदा करता है।

स्त्रियों के प्रति कुंद होतीं जन संवेदनाएं

कनुप्रिया

एक समय था जब निर्भया के लिये पूरा देश हिल उठा था, उसके प्रति इंसाफ़ के लिये सड़कों पर आ गया था, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यहां तक कि कांग्रेस के सत्ताच्युत होने में निर्भयाकांड एक बड़ा कारण बन गया था, जबकि सरकार ने तुरंत उसका अपने ख़र्च पर इलाज कराया, आरोपियों को गिर तार किया, फांसी हुई। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिये न्याय की लड़ाई लड़ी ही जा रही है, उन्नाव की पीड़िता के घाव सूखे नही हैं, हाथरस की पीड़िता के साथ हुआ अन्याय आवाज़ की तलाश में ही है कि कानपुर से 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार की ख़बर आ गई, इस बार बलात्कारी एक यू ट्यूबर और सब इंस्पेक्टर है। सड़क से बच्ची का अपहरण करके, 2 घण्टे उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसे बुरी हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस ने पहले तो प्राथमिकी दज़ ही नहीं की, बाद में सीनियर पुलिस अफसर तक पीड़िता के परिजन पहुंचे तो रिपोर्ट दज़ हुई तब तक बलात्कारी पुलिस वाला फ़रार हो गया।

दुखद ये भी है कि अब ऐसी ख़बरें आती हैं तो हम चौंकते भी नहीं, ये हमारी चेतना को झिंझोड़ता ही नहीं। ऐसी घटनाओं का होना मानो हमारे सामाजिक दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया है। आप गूगल करेंगे तो हर दिन स्त्रियों, बच्चियों के प्रति जघन्य अपराध की कोई न कोई ख़बर मिल ही जायेगी और सबसे ऊपर जिस प्रदेश का नाम मिलेगा वो अपने आप में एक मिनी हिन्दू राष्ट्र है। वहां धर्म के सबसे बड़े ठेकेदारों की डबल इंजन सरकार है।

दरअसल पिछले 11 सालों में जिस योजना पर सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया है वो है बलात्कारी बचाओ योजना। बल्कि जिस शिद्दत से बलात्कारियों को प्रोत्साहन दिया गया है, इसे बलात्कारी बनाओ योजना भी कहें तो अतिशयोक्ति नही होगी, दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। बलात्कारियों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें लगातार ज़मानत दी जाती है (हाल ही में बलात्कारी बाबा आसाराम को 10 महीने में चौथी बार ज़मानत मिली और राम रहीम को 15 वीं बार पैरोल)। जेल से बाहर आने पर बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, कभी उनके पक्ष में भगवा झंडों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। कभी उन पर क़ानून की धार पूरी तरह कुंद हो जाती है, वो ऐसी मार करता है कि अपराधी को चोट ही नहीं लगती। मसलन महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) और 354ए (लैंगिक उत्पीड़न) के तहत %चार्ज फ्रेम' हुए, मगर जांच एजेंसियों ने उन्हें कभी गिर तार ही नहीं किया, 2023 से वो ज़मानत पर हैं, उनकी जमानत का कभी विरोध भी नहीं हुआ। मीडिया ज़्यादातर बलात्कार की घटनाओं पर चुप रहता है, चर्चा नहीं करता, मानो यह सामाजिक चिंता का विषय ही नहीं।

उधर यौन शोषण के प्रति न्यायालयों का रवैया ये है कि न्याय के लिये पीड़िताओं को न्यायालयों के ख़िलाफ़ धरना देने की नौबत आ जाती है। पिछले ही साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और कपड़े उतारने का प्रयास करना, बलात्कार की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी कई शर्मनाक और महिलाओं को न्याय के लिये हतोत्साहित करती हुई टिप्पणियां पिछले कुछ सालों में विभिन्न प्रदेशों के न्यायालयों ने की हैं, जो समाज में बलात्कारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देती हैं।इस सबके बाद त्रासदी ये है कि पीड़िताओं के ख़िलाफ़ ही सोशल मीडिया पर उन्हें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तोड़ने और उनके संघर्ष के प्रति समाज के भीतर नकारात्मक नज़रिया बनाने के लिए अभियान चलाये जाते हैं। मसलन महिला पहलवानों के ख़िलाफ़ ऐसा ही अभियान चलाया गया था कि उनका आंदोलन राजनीतिक है, उनके यौन शोषण की बात झूठ है और आरोपी बिल्कुल निर्दोष है इत्यादि इत्यादि। अब एक अभियान उन्नाव की पीड़िता के विरुद्ध चलाया जा रहा है, एआई के ज़रिए उनके झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनसे ज़ाहिर हो कि वह स्वयं एक बेशरम महिला है और उसने जानबूझ कर आरोपी कुलदीप सेंगर को फंसाया है। तिस पर करेले पर नीम चढ़ा यह कि खुद सरकार बहादुर यौन शोषकों और बलात्कारियों के लिये वोट मांगते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उनके ख़िलाफ़ मामलों पर पूरी तरह चुप्पी मार जाते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य यौन अपराधों पर सरकार ने जिस तरह ख़ामोशी इ तयार की उससे साबित हुआ कि सरकार किस क़दर महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। ज़्यादा जानें सोशल मीडिया परामर्श युवा मनोरंजन खेल उपकरण मु य शीर्षक विशेष रिपोर्ट सदस्यता बॉलीवुड समाचार कविता संग्रह ताज़ा खबरें अपडेट राजनीतिक विश्लेषण पुस्तक साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण आख़िर इससे अधिक प्रोत्साहन बलात्कार को और कैसे दिया जा सकता है? एक बलात्कारी समाज बनाने में सरकार की तरफ़ से कोई कमी रही हो तो बताइए। अब इतना ही बचता है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक मंचों पर यौन शोषकों को समाज के मॉडल की तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। उनके नाम पर पुरस्कार बांटे जायें, उनकी प्रशंसा में पुस्तकें लिखी जायें, सड़कों और स्कूलों के नाम उनके नाम पर रखे जायें, उन्हें पद्म स मान से स मानित किया जाये, ताकि एक स पूर्ण बलात्कारी समाज का लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके, उसे उपलब्धि की तरह दिखाया जा सके। और ये सब हो रहा है घोर सनातनी, धार्मिक सरकारों के राज में, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दंभ भरती हैं और मंदिरों की प्रतिष्ठा पर्व मना–मना कर ही गर्वित हुए जा रही है। धार्मिकता का आलम ये है कि धर्म के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे संत और बाबा लोग स्त्रियों के ख़िलाफ़ अनर्गल बयान देते हैं, जिससे उनकी गरिमा को कड़ी चोट पहुंचती है। मसलन धीरेन्द्र शास्त्री का एक शर्मनाक बयान जिसमें उसने बिना सिंदूर की मांग वाली महिलाओं को ख़ाली प्लॉट की संज्ञा दी गई, जिस पर कोई भी क़ब्ज़ा कर सकता है। बागेश्वर धाम में लड़कियों की तस्करी के आरोप लगे तो बिना जांच किये आरोप लगाने वाले प्रोफेसर के ख़िलाफ़ ही रिपोर्ट दज़ कर ली गई। बाबा अनिरुद्ध आचार्य ने अपने सत्संग में कहा कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, बाबा प्रेमानंद का कहना है कि सौ में से अब 2–4 लड़कियों ही पवित्र होती होंगी। ज़्यादा जानें साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण प्रादेशिक समाचार विविध समाचार युवा मनोरंजन ई–पेपर सदस्यता सोशल मीडिया परामर्श राजनीति समाचार डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ साक्षात्कार संग्रह बजट संबंधित वित्तीय सेवाएँ ये बोल–वचन तब हैं जब देश के अधिकतर बाबाओं पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। यहां तक कि सेलिब्रिटी बाबा सदुरु के आश्रम में भी बच्चों के यौन शोषण के आरोप कई अभिभावकों ने लगाए हैं। मगर धर्मान्ध लोगों की सोचने–समझने की शक्ति इस क़दर छीन लेता है कि फिर भी ये तथाकथित धार्मिक गुरु पूज्य बने रहते हैं। भक्तों में उनकी पद धूलि लेने के लिये ऐसी भगदड़ मचती है कि लोग दब–कुचल कर जान से हाथ धो बैठते हैं, जैसा कि हाथरस के एक गांव में सूरजपाल उफ़ 'भोले बाबा के मामले में हुआ। सच तो ये है कि धर्म एक ऐसा गटर हो चुका है जिसमें समाज के सबसे सड़े हुए, गंदे तबके को प्राणवायु मिलती है, उसके गुनाहों को संरक्षण मिलता है। धर्म, अपराधियों और यौन शोषकों की अंतिम शरणस्थली बन चुका है, तभी तो धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा में अश्लील कंटेंट और घोटालों की आरोपी शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर शामिल होकर स्याह से सफ़ेद हो जाती हैं। एक समय था जब निर्भया के लिये पूरा देश हिल उठा था, उसके प्रति इंसाफ़ के लिये सड़कों पर आ गया था, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यहां तक कि कांग्रेस के सत्ताच्युत होने में निर्भयाकांड एक बड़ा कारण बन गया था, जबकि सरकार ने तुरंत उसका अपने ख़र्च पर इलाज कराया, आरोपियों को गिर तार किया, फांसी हुई और राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को पढ़ाने लिखाने और पायलट बनाने में निजी तौर पर मदद की। मगर इन सबसे भी जनता के भीतर आक्रोश कम नहीं हुआ था। आज उसी देश की जनता की स वेदनाएं स्त्रियों के प्रति मानो कुंद हो गईं, जबकि देश की जनता पहले से ज़्यादा धार्मिक हैं, देश में पहले से कहीं ज़्यादा मंदिर बन रहे हैं और धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं। मगर स्त्रियों पर, मासूम बच्चियों पर यौन शोषण, बलात्कार और हत्या की ख़बरें आती हैं और चली जाती हैं। जनता आक्रोशित नहीं होती, मानो हिन्दू राष्ट्र के लिये स्त्रियों की अस्मिता और गरिमा की बलि स्वीकार्य है, बल्कि ऐसा होना उसने सामान्य मान लिया है।

धार्मिक जलसों का शोर और सर्दी के सितम से मरते लोग

अनिल जैन

शीतलहर, बाढ़ और भीषण गरमी जैसी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई परिघटना नहीं है। यह तो पहले से आती रही है और आती रहेंगी। इन्हें रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है तो इनसे होने वाली जान–माल की तबाही को, जो सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की ईमानदार इच्छाशक्ति से ही संभव है। ताजा शीतलहर और उससे होने वाली मौतें हमें बता रही हैं कि जब मौसम के हल्के से विचलन का सामना करने की हमारी तैयारी नहीं है। सरकारी स्तर पर धार्मिक जलसों और विभाजनकारी भाषणों के बीच इस समय देश के विभिन्न इलाकों में शीतलहर कहर बरपा रही है, जिससे हर साल की तरह देश के विभिन्न इलाकों से लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। अब तक 400 से ज्यादा लोग सर्दी की ठिठुरन से मौत की नींद सो चुके हैं। वैसे इस तरह की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। कहीं भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें तो कहीं गरीबी और कर्ज के बोझ से त्रस्त किसानों और छोटे कारोबारियों की खुदकुशी और कहीं जातीय व सांप्रदायिक हिंसा में होने वाली मौतों के जारी सिलसिले के बीच हर साल ही सर्दी की ठिठुरन, लू के थपेड़ों और बारिश–बाढ़ से भी लोग मरते ही रहते हैं।

मौसम की अति के चलते असमय होने वाली ये मौतें हमारे उस भारत की नग्न सच्चाइयां हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ये सच्चाइयां सिर्फ हमारी सरकारों के शाइनिंग इंडिया, भारत निर्माण न्यू इंडिया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया% %मैक इन इंडिया% जैसे हवा–हवाई कार्यक्रमों और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने जैसे गुलाबी दावों की ही खिल्ली नहीं उड़ाती हैं, बल्कि व्यवस्था पर काबिज लोगों की नालायकी और संवेदनहीनता को भी उजागर करती हैं।

वैसे सर्दी हमारे नियमित मौसम चक्र का ही हिस्सा है। कड़ाके की सर्दी इसका हल्का सा विचलन भर है। सर्दी और भीषण सर्दी अंत में हमें कई तरह से फायदा ही पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की सर्दी हमें आश्वस्त करती है कि ग्लोबल वार्मिंग उतनी सन्निकट नहीं है, जितना कि अक्सर हम मान बैठते हैं। मौसम की मौजूदा अति भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर कुछ साल के बाद हमारा इससे सामना होता रहता है– कभी सर्दी में, कभी गरमी में तो कभी बारिश में।

ज्यादातर भारतीय इस मायने में खुशनसीब हैं कि उन्हें मौसम की विविधताएं देखने को मिलती हैं। अन्यथा दुनिया में ऐसे कम ही इलाके हैं जहां हर मौसम का मज़ा लिया जा सके। प्रत्येक मौसम अपने रौद्र रूप में भी सुंदर होता है, बशर्ते कि उसकी मार से लोगों को बचाने के इंतज़ामात हों। दुनिया में संभवत भारत ही ऐसा देश है, जहां हर मौसम की अति होने पर लोगों के मरने की खबरें आने लगती है। हकीकत यह है कि लोग मौसम की अति से नहीं मरते, वे मरते हैं अपनी गरीबी से, अपनी साधनहीनता से और व्यवस्था तंत्र की नाकामी या लापरवाही की वज़ह से। यूरोप के देशों में सरकारें मौसम की अति का मुकाबला करने के चाक–चौबंद इंतजाम करती हैं, इसलिए वहां लोग हर मौसम का तरह–तरह से लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे देश में भी खाया–अघाया तबका ऐसा ही करता है, जिसके पास हर मौसम की अति का सामना करने और उसका लुत्फ उठाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।

भारत के ज्यादातर हिस्सों में यूरोप जैसी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन हमारे यहां जब हिमालय परिवार की पहाड़ियों पर गिरने वाली बर्फ से मैदानी इलाकों में शीतलहर चलती है तो देश के विभिन्न इलाकों में सर्दी की ठिठुरन से होने वाली मौतों के आंकड़े आने लगते हैं। अभी जो शीतलहर जारी है, वह सिर्फ हिमालयी प्रदेशों और गंगा–यमुना के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और रेगिस्तानी राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और सुदूर छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा तक ठंड से ठिठुर रहे हैं। सर्दी के इस सितम से सामान्य जनजीवन बुरी तरह गड़बड़ा गया है। देश के विभिन्न इलाकों से बेघर लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। हालांकि बड़े शहरों से निकलने वाले समाचारपत्रों में अब सर्दी से होने वाली मौतों की खबरों को जगह मिलनी लगभग बंद हो गई है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। तब अखबारों में नियमित खबरें छपती थी और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट उन खबरों का संज्ञान लेकर संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से जवाबतलब करते थे। उन्हें साधनहीन लोगों के उचित इंतज़ाम करने के निर्देश देते थे। अब सरकारों का मीडिया प्रबंधन तंत्र ऐसी खबरों को छपने से रोकने मे सफल होने लगा है। यही वजह है कि अब कुछ गिने–चुने अखबारों में ही सर्दी से लोगों के मरने की खबरें छपती हैं। टेलीविजन चैनल तो सुबह से रात तक हिंदू–मुसलमान करने में ही व्यस्त रहते हैं। अगर थोड़ी फुरसत मिलती भी है तो उनके लिए अपने दर्शकों को यह बताना ज्यादा जरूरी होता है कि फलां अभिनेत्री कब शादी करने वाली है, फलां अभिनेत्री कब मां बनने वाली है और किस अभिनेत्री का किस अभिनेता से तलाक होने वाला है या फिर वे यह बताते हैं कि लोग सर्दी का लुत्फ़ लेने के लिए क्या–क्या कर रहे हैं और कहां–कहां जा रहे हैं।

सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 800 से ज्यादा लोग सर्दी के सितम से मरते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2015 में 1149 लोगों की मौत हुई थी। हकीकत यह है कि अगर समूचे भारत के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो हर साल सर्दी से मरने वालों की सं या हजारों में पहुंचती है। ज्यादातर मौतें बड़े शहरों और महानगरों में होती हैं। जो मरते हैं, उनमें से ज्यादातर बेघर होते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में दूरदराज़ के इलाकों से अपने ही राज्य में या दूसरे राज्यों के बड़े शहरों या महानगरों में जाते हैं, ताकि मेहनत–मजदूरी कर अपने परिवार के जिंदा रह सकने लायक कुछ कमा सकें। मौसम कोई भी हो, जब भी उसकी अति दरवाजे पर दस्तक देती है तो हमारी सारी व्यवस्थाओं की पोल का पिटारा खुलने लगता है। फिलहाल सर्दी की बात की जाए तो हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा पोल खुली है पूर्वानुमान लगाने वाले मौसम विभाग की। बारिश का मौसम खत्म होते ही हमें बताया गया था कि इस बार सर्दी कम पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाओं के बीच इस भविष्यवाणी पर किसी को भी हैरानी नहीं हुई थी, परन्तु जैसे ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो फिर मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि यह कड़ाके की ठंड चंद दिनों की ही मेहमान है। जल्द ही मौजूदा उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान सामान्य के करीब पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा जानें युवा मनोरंजन समाचार पत्र वितरण सेवा विदेश यात्रा योजनाएँ प्रादेशिक समाचार हिंदी भाषा शिक्षण मनोरंजन पत्रिका खेल उपकरण संपादकीय लेख सोशल मीडिया परामर्श कविता संग्रह सिर्फ मौसम विभाग ही नहीं, बाकी सरकारी महकमों का भी यही हाल है। फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और भूमिगत पारपथों पर रात गुजारने वाले बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था अभी भी कई जगह अधूरी है या बिल्कुल ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कई बार इस मामले में राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पु ता बंदोबस्त करने के निर्देश दे चुका है। जहां रैन बसेरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है, वहां अलाव जलाने के लिए लकड़ी मुहैया कराई जाती है, लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों में मौसम की मार से लोगों के मरने के पीछे सबसे बड़ी वजह है शहरी नियोजन में सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता। जब से आवासीय कॉलोनियों की बसाहट के मामले में विकास प्राधिकरणों और गृह निर्माण मंडलों के बजाय निजी भवन निर्माताओं और कॉलोनाइज़रों का दखल बढ़ा है, तब से रोज कमाकर रोज खाने वालों और बेघर लोगों के लिए आवासीय योजनाएं हाशिए पर खिसकती गई हैं। करोड़ों लोग आज भी फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर और टाट या प्लास्टिक आदि से बनी झोपड़ियों में रात बिताते हैं। बहुत से लोगों के पास तो पहनने को गरम कपड़े या ओढ़ने को रजाई–कंबल तो दूर तापने को सूखी लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को मौसम की मार से बचाने के लिए अदालतें हर साल सरकारों और स्थानीय निकायों को लताड़ती रहती हैं, लेकिन सरकारीतंत्र की मोटी चमड़ी पर ऐसी लताड़ों का कोई असर नहीं होता है। शीतलहर, बाढ़ और भीषण गरमी जैसी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई परिघटना नहीं है।

विविध समाचार

पर्यटन के मानचित्र पर कांगड़ा जिले को मिलेगी नई पहचान : मुकेश अग्निहोत्री

धर्मशाला १५/०७ (संवाददाता): उप– मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित जिला स्तरीय 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सेना, पुलिस, होम गार्ड्स, एनएसएस और स्काउट एवं गाइड्स की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत शानदार परेड की सलामी ली। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए संसाधनों के सृजन पर बल दिया गया है जिसके कारण पिछले तीन वर्षों में 26 हजार 683 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला में ही पर्यटन निगम का राज्य मुख्यालय स्थान्तिरत किया गया है। देहरा के बनखंडी में 619 करोड़ की लागत से अरण्य वन्यप्राणी उद्यान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले के नड्डी में एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन स्थापित की जाएगी जिसकी कुल लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी और इसे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल तरीके से तैयार किया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके रनवे की लंबाई को 1376 मीटर से बढ़ाकर इसे 3010 मीटर किया जाएगा यहां एयरबस एवं रात्रि लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और 1332 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पालमपुर में हेलिपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। पौंग क्षेत्र में पर्यटन, वॉटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार एनआईटी हमीरपुर विशेषज्ञों के सहयोग से ज्वालामुखी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर कार्य कर रही है जिस के लिए 100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है जबकि शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 150 करोड़ रूपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि देहरा उप–मंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ई–टैक्सी खरीदने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में बेहतर पेयजल और सिंचाई के लिए सरकार ने 354 योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें से 192 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन योजनाओं के लिए 3360 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लिए 213.40 करोड़ रुपये की सुकाहार मध्यम सिंचाई परियोजना तथा ज्वालामुखी क्षेत्र की पंचायतों के लिए 333.49 करोड़ रुपये की पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में 9 सीवरेज योजनाओं के लिए 433.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और 93.52 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना के लिए कुल स्वीकृत 643.68 करोड़ रुपये में से 301.48 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुरानी डीजल बसों के स्थान पर 297 नई विद्युत बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जा रही हैं जिस पर 424 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राज्य के विश्राम गृहों तथा सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 310 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार 41 अन्य स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) भी विकसित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के कंदरोडी में 268 करोड़ रूपये की लागत से नया पेप्सी प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसमें 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पशु पालकों की आय में बढ़ोतरी के लिए कांगड़ा में ढगवार में 201 रुपये करोड़ रूपये की लागत से विश्वस्तरीय दूध प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उप–मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आहवान किया कि युवाओं में नशे के बढ़ते चलन के खिलाफ समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए ताकि युवाओं का भविष्य अंधकारमय न हो। सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियायन चलाया है और नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दलों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रत्न, आशीष बुटेल और विधायक मलेंद्र राजन, प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, एपीएमसी के चेयरमैन नीशू मोंगरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा, नगर निगम महापौर नीनू शर्मा, पूर्व महापौर देवेन्द्र जग्गी, पार्षद अनुराग, ओंकार नेहरिया, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित थे।

श्री गुरु रविदास जी के समानता के संदेश को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए पंजाब सरकार की अनूठी पहल

चंडीगढ १५/०७ (संवाददाता): छह सदियों पहले श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने तथा उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके तहत जालंधर जिले में डेरा बल्लां के निकट श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 10 करोड़ रुपये की लागत से कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम दर्ज की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री चीमा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए आज कुल तीन रजिस्ट्रियां क्रमशः गाँव नौगजा (64 कनाल 5 मरलेकृलागत 5,40,98,500 रुपये), गाँव फरीदपुर की पहली रजिस्ट्री (2 कनालकृलागत 16,74,000 रुपये) तथा गाँव फरीदपुर में दूसरी रजिस्ट्री (10 कनाल 14 मरलेकृलागत 1,44,62,150 रुपये) की गई हैं। उन्होंने बताया कि कुल तीनों रजिस्ट्रियों का क्षेत्रफल 76 कनाल 19 मरले है और कुल लागत 7,02,54,659 रुपये है। स चीमा ने कहा, "हमें इस नेक कार्य में योगदान देने पर गर्व है। हमारी सरकार श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रचारित समानता, करुणा और सामाजिक न्याय के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए समर्पित है।" उन्होंने आगे कहा, "यह अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ सिद्ध होगा।" इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना और सामाजिक–आर्थिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य सेमिनारों, प्रकाशनों और समुदाय–आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का शोध, संरक्षण और प्रचार करना है।

विधायक परगट सिंह ने सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच संगतों को दी गुरुपर्व की शुभकामनाएं, लिया संतों का आशीर्वाद

जालंधर १५/०७ (संवाददाता): पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह वीरवार को श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें गुरुपर्व के मौके पर बनारस (वाराणसी) के लिए रवाना हुई ट्रेन को लेकर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने डेरा सचखंड बल्लां के गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और बनारस जाने वाली संगतों को गुरुपर्व की शुभकामनाएं दीं।उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का रास्ता दिखाया है। उनके दिए गुरु रविदास जी का जीवन उपदेश समाज को एकता और सेवा के लिए प्रेरित करता हैं। उन्होंने कहा कि गुरुपर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालु हर साल गुरु महाराज की जन्मस्थली बनारस (वाराणसी) में मत्था टेकने जाते हैं। यह परंपरा वर्षों से श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। उनके साथ कांग्रेसी नेता सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जिला प्रधान शहरी रजिंदर बेरी, विधायक सुखविंदर कोटली और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर भी अन्य नेता भी शामिल रहे।

भक्ति आंदोलन के सूर्य संत शिरोणि रविदास

भारतीय इतिहास का मध्यकाल (15वीं–16वीं शताब्दी) न केवल राजनीतिक उथल–पुथल का दौर था, बल्कि तत्कालीन भारत एक गहरे वैचारिक संक्रमण काल से भी गुजर रहा था। एक ओर विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से भारतीय समाज अपनी रक्षात्मक मुद्रा में था, वहीं दूसरी ओर आंतरिक रूप से जातिवाद, छुआछूत और विद्वता नहीं बल्कि जन्मना ब्राह्मणवाद की कट्टरता ने समाज को खोखला कर दिया था। ऐसे अंधकारमय समय में काशी की धरती पर विक्रम संवत 1433 में माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास का प्रकटीकरण केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक मानवीय क्रांति का सूत्रपात था।इस आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के कालखंड में संत रविदास (जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है) एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बनकर उभरे, जिन्होंने धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं को चुनौती दी और भक्ति को कर्मकांडों के चंगुल से मुक्त कर सीधे मानवतासे जोड़ दिया। उनका जीवन और दर्शन आज भी सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला माना जाता है। उन्होंने धर्म को मंदिर–मस्जिद की दीवारों से निकालकर इंसानियतकी चौखट पर ला खड़ा किया।

संत रविदास का जन्म वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर ग्राम में विक्रम संवत 1433 में माघ पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता संतोख दास और माता कलसां देवी थे। वे एक चर्मकार परिवार से संबंधित थे। तत्कालीन समाज में इस कार्य को करने वाली जातियों को अछूत और हेय दृष्टि से देखा जाता था।लेकिन संत रविदास ने अपने पैतृक व्यवसाय (जूते बनाना) को कभी नहीं त्यागा। उन्होंने सिद्ध किया कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने वाली नियत महत्वपूर्ण होती है। वे जूते गांठते हुए भी ईश्वर का सिमरन करते थे। यही उनके जीवन का पहला बड़ा सुधार था–श्रम की गरिमाकी स्थापना।उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। रामानंद के सान्निध्य व प्रभाव से रविदास कीआध्यात्मिक दृष्टि व्यापक हुई, जहां उन्होंने सीखा कि जाति–पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।रविदास का स्वामी रामानंद का शिष्य बनना मध्यकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। रामानंद ने जाति–पाति पूछे नहीं कोई का जो नारा दिया था, रविदास उसके जीवंत उदाहरण बने।कहा जाता है कि जब रविदास ने रामानंद से दीक्षा मांगी, तो काशी के पंडितों ने इसका विरोध किया। तब रामानंद ने उनके अंतर्मन की शुद्धि को देखकर उन्हें अपनाया। रविदास ने गुरु से प्राप्त ज्ञान को अपनी कर्मस्थली जूते बनाने की दुकानपर ही चरितार्थ किया। उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर को पाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपना कर्म करना ही तपस्याहै।उन्होंनेसामाजिक सुधार के लिए जातिवाद पर प्रहार और समानता का शंखनाद किया।रविदास का सबसे बड़ा योगदान जातिआधारित ऊँच–नीच के विरुद्ध उनका साहसी संघर्ष था। उन्होंने शास्त्रों की उन दकियानूसी व्याख्याओं को नकारा जो मनुष्य को जन्म के आधार पर विभाजित करती थीं।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की–

रैदास जन्म के कारनै, होत न कोई नीच।
नर को नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच।।

अर्थात– मनुष्य जन्म से नीच नहीं होता, बल्कि उसके बुरे कर्म ही उसे नीच बनाते हैं।

उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान और पंच तत्वों से निर्मित हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि सबका सृजनहार (ईश्वर) एक है, तो इंसानों में भेद कैसा? उनके इस दर्शन ने समाज के वंचित वर्गों में आत्म–सम्मान का संचार किया। रविदास ने अपनी वाणी में एक ऐसे आदर्श शहर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। यह केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक घोषणापत्र था।उनके अनुसार बेगमपुरा अर्थात बिना–गम का शहर एक ऐसा स्थान है, जहां दुःख व चिंता (तसवीस) का नामोनिशान नहीं है।कोई कर (खिराज) या संपत्ति का भय नहीं है।कोई सामाजिक भेदभाव या ऊँच–नीच नहीं है।सभी नागरिक समान हैं और कहीं भी आने–जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि थॉमस मोर की यूटोपियासे सदियों पहले, रविदास ने एक ऐसे संप्रभु और समतावादी समाज का खाका खींचा था, जो आज के आधुनिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्यके सिद्धांतों से मेल खाता है। रविदास की भक्ति निर्गुणथी, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम अत्यंत सगुण और गहरा था।उनका प्रसिद्ध सूत्र– मन चंगा तो कठौती में गंगा– बाहरी दिखावों, तीर्थ यात्राओं और कर्मकांडों पर सबसे बड़ी चोट थी। उन्होंने सिखाया कि यदि आपका मन पवित्र है और कर्म ईमानदारी भरा है, तो आप जिस बर्तन (कठौती) में काम कर रहे हैं, उसी में गंगा का पुण्य प्राप्त हो सकता है।उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर मेवाड़ की रानी मीराबाई ने रविदास को अपना गुरु बनाया था। एक चर्मकार संत को एक क्षत्रिय रानी द्वारा गुरु स्वीकार किया जाना मध्यकाल की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। यह इस बात का प्रमाण था कि ज्ञान और भक्ति किसी जाति की बपौती नहीं हैं।

संत रविदास की वाणी सरल, सहज और हृदय को छूने वाली थी। उनकी रचनाओं ने धर्म और भाषा की सीमाओं को तोड़ दिया।उनकी भाषा सरल ब्रज, अवधी और राजस्थानी का मिश्रण है, जिससे वे आम जनता से सीधे जुड़ सके। उनकी वाणी में करुणाऔर विद्रोहका अद्भुत संतुलन है। उनकी आध्यात्मिक महानता, उनके साहित्यिक विरासत की व्यापक स्वीकार्यताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके 40 पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिखों के पंचम गुरु, गुरु अर्जुन देव सिंह ने उनकी वाणी को गुरुओं के बराबर सम्मान दिया।उनके पदों में ईश्वर के प्रति समर्पण, विरह और सामाजिक चेतना का अद्भुत मिश्रण है। वे स्वयं को खलास चमारा अर्थात मुक्त चमार कहते थे, जो जाति के बंधनों से ऊपर उठ चुका था।वर्तमान में भी संत रविदास केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं।पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया है, जिसे रविदासिया धर्मके रूप में जाना जाता है।भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉ. बी.आर. अंबेडकर रविदास के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। संविधान में वर्णित समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य कहीं न कहीं रविदास के बेगमपुराके सपने का ही विस्तार हैं।

संत रविदास का जीवन इस बात का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों और सामाजिक भेदभाव के बावजूद, मनुष्य अपने चरित्र और कर्म से सर्वोच्चता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भक्ति को परलोकसे हटाकर इहलोक(इस संसार) के सुधार से जोड़ा। उनका नारा– रैदास मनुष ना जुड़ सके, जब लौ जाति न जात– आज के खंडित समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी और समाधान है।जब तक संसार में गरीबी, भेदभाव और अन्याय रहेगा, संत रविदास का बेगमपुरामानवता का अंतिम लक्ष्य बना रहेगा। वे केवल एक समुदाय के संत नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मानवतावादी पथप्रदर्शकहैं।मध्यकालीन भारत की वैचारिक पृष्ठभूमि में बेगमपुरा को मानवीय चेतना का वैश्विक घोषणापत्र और सामाजिक क्रांति का महाकाव्य कहा जा सकता है।संत रविदास का जीवन जहां चर्मकार कुल का संघर्ष का प्रतीक हैं, वहीं प्रतिकूलताओं के बीच प्रज्ञा का उदय का भी द्योतक है।जिस काल में शूद्रों के लिए वेद सुनना भी अपराध माना जाता था, उस काल में एक चर्मकार परिवार में जन्म लेकर ब्रह्म–ज्ञानप्राप्त करना अपने आप में एक विद्रोह था। रविदास ने बचपन से ही सामाजिक अपमान को देखा, लेकिन उनके भीतर घृणा के बजाय करुणाका संचार हुआ।वे बचपन से ही साधु–संतों की सेवा में लगे रहते थे। कथाओं के अनुसारवे अक्सर अपने पिता द्वारा दिए गए धन से भूखे साधुओं को भोजन करा देते थे। उनकी यह परोपकारी प्रवृत्ति आगे चलकर उनके व्यापक मानवतावाद का आधार बनी।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, गुरूवार 16 जुलाई 2026 | पृष्ठ-6

आईजीएच में 14 साल की लड़की दुर्लभ गिलेन-बैरे सिंड्रोम से हुई ठीक

राउरकेला १५/०७ (संवाददाता): एक उल्लेखनीय चिकित्सा उपलज़्धि में, सेल, राउरकेला इस्पात सयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) के डॉज़्टरों ने दुर्लभ और जानलेवा गिलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) से पीड़ित 14 वर्षीय लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिससे वह 35 दिनों के श्वसन सहायता से गुज़रने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। राउरकेला के निवासी स्वयं सिद्धा पाढ़ी को 10 जून, 2026 को पेट में इन्फेज़्शन के बाद कमजोरी, शरीर में दर्द, गले में खराश और पीठ दर्द की शिकायत के साथ आईजीएच में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप चारों अंगों में गंभीर कमजोरी और श्वसन संकट हुआ। विस्तृत नैदानिक मूल्यांकन के बाद, उसे गिलेन-बैरे सिंड्रोम का निदान किया गया, एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल

विकार जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय नसों पर हमला करती है। आईजीएच में बहु-विषयक टीम ने तुरंत गहन उपचार शुरू किया। चूंकि बीमारी ने उसकी श्वसन की मांसपेशियों को प्रभावित किया, इसलिए उसे 35 दिनों के लिए ट्रेकियोस्टोमी के माध्यम से लंबे समय तक वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। निरंतर गंभीर देखभाल, उचित चिकित्सा प्रबंधन, फिजियोथेरेपी और समर्पित नर्सिंग सहायता के साथ, रोगी ने धीरे-धीरे मांसपेशियों की ताक़त और श्वसन कार्य को पुन: प्राप्त किया।

निरंतर सुधार के बाद, ट्रेकियोस्टोमी को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया था। मरीज़ ने अब अपने अंगों में पूरी ताक़त हासिल कर ली है, स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है, एक सामान्य आहार का सेवन कर रही है और स्वस्थ स्थिति में छुट्टी दे दी गई है। यह सफल इलाज आईजीएच के मुज़्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, डॉ. जयंत कुमार आचार्य की देखरेख में किया गया। टीम में विभागाध्यक्ष (बाल चिकित्सा), डॉ. अर्चना बेहरा, विभागाध्यक्ष (आईसीयू और एनेस्थीसिया), डॉ. संजुक्ता पाणिग्रही, डॉ. अनीता लकड़ा, डॉ. सुप्रभा प्रधान, डॉ. तेजमयी गोपे, डॉ. पी. जे. रॉय और आईसीयू की वरिष्ठ सलाहकार टीम, उप मुज़्य चिकित्सा अधिकारी (ईएनटी), डॉ. गौतम दास साथ ही सिस्टर शाइनी जॉर्ज और नर्सिंग टीम शामिल थे, जिनकी समर्पित कोशिशों से मरीज़ का सफल इलाज संभव हो सका।

अपना आभार व्यक्त करते हुए, मरीज़ के परिवार ने डॉज़्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों को उनके विशेषज्ञ उपचार, प्रतिबद्धता और लंबे समय तक अस्पताल में चले इलाज के दौरान सहानुभूतिपूर्ण देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। इस जटिल मामले का सफल प्रबंधन समन्वित बहु-विषयक देखभाल के माध्यम से महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा और न्यूरोलॉजिकल आपात स्थितियों को संभालने में आईजीएच की उन्नत क्षमताओं को दर्शाता है। यह क्षेत्र के लोगों को गुणवज़ापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को भी मज़बूत करता है।

संबलपुर में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 32 किलो गांजा के साथ चार को धर-दबोचा

संबलपुर १५/०७ (संवाददाता): संबलपुर जिला के रेढ़ाखोल आबकारी टीम ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के दो और ओडिशा के कटक जिला के दो तस्करों को 32 किलो गांजा और एक टाटा इंडिगो कार के साथ गिरज़्तार किया।

यह चारों आरोपित बऊद जिला से गांजा लेकर रेढ़ाखोल के रास्ते पश्चिम बंगाल जा रहे थे। चारों के खिलाफएनडीपीएस एज़्ट के तहत अपराध दर्ज कर बुधवार के दिन न्यायिक हिरासत में रेढ़ाखोल उपकारा भेज दिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए रेढ़ाखोल आबकारी इंस्पेज़्टर जाधव पधान ने बताया कि मंगलवार की आधी रात जब आबकारी टीम गश्ती पर निकली थी तभी रेढ़ाखोल थाना अंतर्गत बिशीपाली चौक के निकट बऊद जिला के ओर से आती सफेद रंग की एक टाटा इंडिगो कार को रोककर तलाशी ली तब दो बड़े प्लास्टिक बैग में भर्ती 32 किलो गांजा मिला।

ऐसे में कार में सवार चार व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद बुधवार के दिन चारों को गिरज़्तार कर लिया गया।

उधरए राउरकेला के किंजिरकेला थाना क्षेत्र के बेहराडीह पंचायत के जड़ाकुदर गांव में 26 वर्षीय दिलीप इंदुआर की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को जज़्त किया गया एवं इसकी जांच शुरु की गई है। रात को भोजन करने के बाद वह सोने चला गया था।

देर सुबह तब वह चारपाई पर पड़ा था। जब परिवार वालों को इसका पता चला तो उसे इलाज के लिए सुंदरगढ़ सरकारी अस्पताल ले गए।वहां चिकित्साकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किंजिरकेला पुलिस द्वारा शव को कज़्जे में लेने के बाद उसका पंचनामा व पोस्टमार्ट कराने के बाद स्वजनों को सौंपा गया।

वन विभाग ने बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए

संबलपुर १५/०७ (संवाददाता): बिजली के झटके से तीन हाथियों की मौत के बाद संबलपुर वन विभाग ने लगातार मानव.पशु संघर्षों के बीच हाथियों की मौतों को रोकने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। मानव और हाथियों के बीच बढ़ता संघर्ष वन विभाग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। फसल कटाई के मौसम मेंए हाथी अज़्सर गांवों में घुस आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण ग्रामीणों ने बिना सोचे.समझे अपनी फसलों की रक्षा के लिए अनैतिक तरीके अपनाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतत: हाथियों की मौत हो जाती है। प्रभावी समाधानों की कमी के कारण मानव.हाथी संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा हैए खासकर संबलपुर डिवीजन में। हाल ही में हुई एक त्रासदीए जिसमें नकटीदेउला वन रेंज के अंतर्गत बुरोमल के पास उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के संपर्क में आने से तीन हाथियों की मौत हो गईए ने वन अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इसे व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया है। संबलपुर क्षेत्रीय मुज़्य वन संरक्षक ;आरसीसीएफटी अशोक कुमार ने कहा कि वन क्षेत्रों में गश्ती दलों को बढ़ाया गया है और हाथियों की महत्वपूर्ण आवाजाही वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्ती उपाय किए गए हैं।

लगभग 120 वन कर्मियों को विभिन्न स्थानों पर गश्त करने के लिए नियुक्त किया गया है। हाथियों के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों मेंए विशेष रूप से रेडाखोल वन प्रभाग मेंए 124 संवेदनशील गाँवों ;हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। वन अधिकारीए टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीज़्यूशन लिमिटेड ;टीपीडज़्ल्यूओडीएल कर्मियों के सहयोग सेए अवैध बिजली कनेज़्शन और हुकिंग जैसे अनधिकृत विद्युत सेटअप की जाँच के लिए नियमित निरीक्षण कर रहे हैं।

जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने के लिएए 400 समुदाय के सदस्योंए जिन्हें गजसाथी के रूप में जाना जाता हैए को हॉटस्पॉट में लगाया गया है। उन्हें हाथियों की गतिविधि की निगरानी, धान के खेतों की सुरक्षा और अवैध बिजली कनेज़्शन और हाथी से संबंधित जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का काम सौंपा गया है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य मानव.हाथी संघर्ष को कम करना और क्षेत्र में स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अवैध बिजली कनेज़्शन के परिणामों, इस तरह की कार्रवाइयों से जुड़े दंड और वन्यजीवों द्वारा फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपलज़्ध सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्तए निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे गाँवों या धान के खेतों के पास हाथियों को देखकर घबराएँ नहीं। इसके बजायए उन्हें तुरंत वन अधिकारियों या ष्जसाथियोंष् जैसे प्रशिक्षित हाथी प्रतिक्रिया दलों को सूचित करने की सलाह दी जाती है। वन विभाग हाथियों और अन्य जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में जिज़्मेदारी लेने और सहयोग करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को भी शामिल कर रहा है। उपलज़्ध आंकड़ों के अनुसारए संबलपुर वन मंडल ने पिछले वर्ष सात हाथियों की मौत दर्ज कीए जिनमें संबलपुर और रेधाखोल वन प्रभागों में तीन.तीन और बरगढ़ वन प्रभाग में एक शामिल है। दुखद रूप सेए छह वन प्रभागों के अंतर्गत हाथियों के हमलों के कारण 10 लोगों की मौत के साथ मानवीय मौतें भी हुई हैं।

बणई अनुमंडल में पर्यटन स्थलों की उपेक्षा

राउरकेला १५/०७ (संवाददाता): प्राकृतिक मनोरम स्थलों से परिपूर्ण बणई अनुमंडल में पर्यटन की उपेक्षा की जा रही है। पर्यटन विभाग व वन विभाग की ओर से खंडाधार जलप्रपातए देवधरए तथा कोइड़ा में प्राकृतिक पर्यटन स्थल के विकास के लिए काम हुआ है पर अब भी गुरुंडिया के बादल गिरि जलप्रपातए ब्राह्मणी नदी में सिचाई परियोजनाए सरसरा में सिचाई परियोजनाए कोइड़ा में कुराड़ी नाले में सिचाई परियोजना का काम कर आसपास के क्षेत्र में पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं। गुरुंडियाए लहुणीपाड़ाए कोइड़ व बणई ज़्लाक के जल प्रपात हैं जिनका विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जा सकता है। सुंदरगढ़ जिले में बणई अनुमंडल में ही ओडिशा का सबसे ऊंचा जलप्रपात खंडाधार स्थित है। राज्य सरकार की ओर से यहां पर्यटको को आकृष्ट करने के लिए इको टूरिज़्म में शामिल किया गया है तथा इस क्षेत्र में वन विभाग की ओर से विकास का काम किया जा रहा है।

टेनसा में पहाड़ी की ऊंचाई पर गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं एक महीने के अंदर आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जायेगा। ब्राह्मणी नदी पर दार्जिंग घाटए वीरतोला घाट के साथ रुकड़ा सिचाई परियोजनाए सरसरा में बड़जोर सिचाई परियोजनाए कोइड़ा ज़्लाक में कुराली सिचाई परियोजना के आसपास पर्यटन विकास के लिए पर्याप्त संभावना है। इसके अलावा बणईए गुरुंडियाए लहुणीपाड़ा व कोइड़ा ज़्लॉक क्षत्र में घागए मिरिग लेउटुणीए बादलगिरिए घोराघरए खंभेश्वरीए सूखानालाए मानसमुंडी आदि जल प्रपात लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं।

आरएसपी के भावी विस्तारण हेतु स्थानांतरण के लिए चिन्हित 514 परिवारों को 21.17 करोड़ रुपये से अधिक की विज़ीय सहायता प्रदान

राउरकेला १५/०७ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) अपनी वर्तमान 4.65 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 9.8 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के उद्देश्य से अपनी वर्तमान इकाइयों से सटी भूमि पर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक विशाल ग्रीनफील्ड विस्तारण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार है। इस दूरदर्शी विस्तारण परियोजना को साकार करने के लिए आरएसपी की चिन्हित भूमि पर स्थित झुग्गियों में निवासरत लोगों को विज़ीय सहायता के साथ-साथ देवगांव के निकट आवासीय भूखंड, संविदा रोजगार तथा चिकित्सा सुविधाएँ उपलज़्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, उनके सुगम स्थानांतरण के लिए अस्थायी आश्रय (ट्रांजिट आवास) की व्यवस्था भी की गई है।

अब तक स्थान्तरित 514 परिवारों को 21.17 करोड़ रुपये से अधिक की विज़ीय सहायता प्रदान की जा चुकी है, जबकि 200 व्यक्तियों को संविदा रोजगार उपलज़्ध कराया गया

है। इसके अलावा, 318 झुग्गियों में रहने वाले परिवार पहले ही अस्थायी आश्रय अथवा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। देवगांव के निकट विकसित किए जा रहे पुनर्वास स्थल पर तीव्र गति से विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ आवासीय भूखंडों के साथ-साथ सड़क संपर्क, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था तथा जल निकासी प्रणाली जैसी आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत भूखंडों का औपचारिक रूप से संबंधित परिवारों को आवंटन किया जाएगा।

वर्तमान में राउरकेला इस्पात संयंत्र में लगभग 12,000 प्रत्यक्ष तथा 12,000 अप्रत्यक्ष कर्मी कार्यरत हैं। नियमित कर्मचारियों में 87 प्रतिशत से अधिक ओडिशा राज्य से हैं, जिनमें कुल श्रमशक्ति का लगभग 28 प्रतिशत सुंदरगढ़ जिले से संबंधित है। भारी उद्योगों की दुनिया में एक इस्पात संयंत्र का 1ः10 गुणक प्रभाव माना जाता है, अर्थात संयंत्र में कार्यरत प्रत्येक एक व्यक्ति के साथ परिवहन, लॉजिस्टिज़्स तथा सेवा क्षेत्रों में लगभग दस अन्य लोगों की आजीविका भी जुड़ी होती है। जैसे-जैसे इस्पात संयंत्र अपनी क्षमता में भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है, इससे बड़ी संज़्या में कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, विस्तार का यह चरण स्थानीय व्यापार में बदलाव लाते हुए पूरे क्षेत्र में खुशहाली की लहर लाकर, इलाके की आर्थिक तस्वीर को एक बार फिर से बदल देगा।

भारतीय थल सेना

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER

www.joinindianarmy.nic.in

अधिकारी प्रविष्टियाँ

1. निम्नलिखित कोर्सों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं:-

(क) **125वां** अल्पकालिक सेवा कमीशन जे.ए.जी. कोर्स अप्रैल 2027, कानून में स्नातक पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए।

(ख) **125वां** अल्पसेवा कमीशन एन.सी.सी. विशेष भर्ती कोर्स (पुरुष) (युद्ध में हताहत सेना कर्मियों के आश्रित सहित) अप्रैल 2027 के लिए।

(ग) **125वां** अल्पसेवा कमीशन एन.सी.सी. विशेष भर्ती कोर्स (महिला) (युद्ध में हताहत सेना कर्मियों के आश्रित सहित) अप्रैल 2027 के लिए।

2. ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित अवधि तक खुले रहेंगे:-

(क)	जे.ए.जी. कोर्स	- पुरुष एवं महिला	-	17 जुलाई से 17 अगस्त 2026
(ख)	एन.सी.सी. विशेष भर्ती कोर्स	- पुरुष	-	20 जुलाई से 20 अगस्त 2026
(ग)	एन.सी.सी. विशेष भर्ती कोर्स	- महिला	-	21 जुलाई से 21 अगस्त 2026

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-

(a) **125th** Short Service Commission (JAG) Entry Course (Men & Women) Apr 2027 course for Law Graduates.

(b) **125th** Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2027 for Men (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).

(c) **125th** Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2027 for Women (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).

2. Online applications will open as under:-

(a)	JAG Course	- Men & Women	-	17 Jul to 17 Aug 2026
(b)	NCC (Special) Course	- Men	-	20 Jul to 20 Aug 2026
(c)	NCC (Special) Course	- Women	-	21 Jul to 21 Aug 2026

नोट :

1. सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है। दलालों से सावधान रहें।
2. विस्तृत नोटिफिकेशन के लिये कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

Note:

1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0011/2627